



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 5, 2010/वैशाख 15, 1932

No. 233]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 5, 2010/VAISAKHA 15, 1932

गृह मंत्रालय

(सी एस प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2010

सा.का.नि. 380(अ).—कैदी सम्प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (2003 का 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध बंगलादेश गणराज्य की सरकार के लिए लागू होंगे तथा भारत गणराज्य की सरकार और बंगलादेश लोक गणराज्य की सरकार के बीच हुई संधि के पाठ को निम्न प्रकार अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

“दण्डित व्यक्तियों के अन्तरण के संबंध में भारत-गणराज्य की सरकार तथा बंगलादेश लोक-गणराज्य की सरकार के बीच करार”

भारत-गणराज्य की सरकार तथा बंगलादेश लोक-गणराज्य की सरकार, जिन्हें इसमें इसके बाद संविदाकार देश कहा गया है;

दण्डित व्यक्तियों का उनके स्वयं के देशों में सामाजिक पुनर्वास सुगम बनाने की अभिलाषा से; और

यह मानते हुए कि यह उद्देश्य, कोई अपराध करने के परिणामस्वरूप दोषसिद्ध और दंडित किए गए विदेशी नागरिकों को उनके स्वयं के समाज में अपनी सज़ा काटने का अवसर प्रदान करके पूरा किया जाना चाहिए;

निम्न प्रकार सहमत हो गई हैं :

अनुच्छेद 1परिभाषा

इस करार के उद्देश्य हेतु :

- (क) “निर्णय” से तात्पर्य न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के किसी ऐसे निर्णय अथवा आदेश से है जिसके तहत दण्ड दिया गया हो;
- (ख) “प्राप्तकर्ता देश” से तात्पर्य उस देश से है जिसको दण्डित व्यक्ति सज़ा काटने के प्रयोजन से अंतरित किया जा सकता हो अथवा अंतरित किया गया हो;
- (ग) “दण्ड” से तात्पर्य किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा अपने दंडिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए निर्धारित समयावधि के लिए या आजीवन के लिए स्वतंत्रता से वंचित रखे जाने का कोई दंड या उपाय है;
- (घ) “दण्डित व्यक्ति” से तात्पर्य किसी दंडिक न्यायालय, जिसमें संविदाकार देशों में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा स्थापित न्यायालय भी शामिल हैं, द्वारा पारित किसी आदेश के तहत कारावास की सज़ा काट रहे व्यक्ति से है;
- (ङ) “अंतरणकर्ता देश” से तात्पर्य उस देश से है जिसमें उस व्यक्ति को दंड दिया गया हो जिसे अंतरित किया जा सकता है या जिसे अंतरित कर दिया गया हो।

अनुच्छेद 2सामान्य सिद्धांत

- (1). इस करार के प्रावधानों के अनुसार किसी संविदाकार देश के भू-भाग में दंडित किसी व्यक्ति को सज़ा काटने के लिए दूसरे संविदाकार देश के भू-भाग में अंतरित किया जा सकता है ताकि वह उसे दी गई सज़ा काट सके। इस संबंध में दंडित व्यक्ति इस करार के अंतर्गत अन्तरणकर्ता देश अथवा प्राप्तकर्ता देश से ऐसे अंतरण के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है।
- (2). अन्तरण का अनुरोध किसी दंडित व्यक्ति द्वारा, जो किसी संविदाकार देश का नागरिक है, अथवा संविदाकार देशों के कानून के अनुसार उसके स्थान पर कार्य करने के हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, संविदाकार देश को उसके द्वारा निर्धारित किए गए तरीके से आवेदन प्रस्तुत करके किया जा सकता है।

### अनुच्छेद 3 अंतरण की शर्तें

(1). इस करार के अंतर्गत किसी दंडित व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर ही अन्तरित किया जा सकता है :

- (क) वह व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का नागरिक हो;
- (ख) दंडित व्यक्ति को मृत्युदण्ड नहीं दिया गया हो;
- (ग) निर्णय अंतिम हो;
- (घ) अन्तरणकर्ता देश में दंडित व्यक्ति के विरुद्ध कोई जांच, अथवा किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही लम्बित नहीं हो;
- (ङ) अंतरण के अनुरोध की प्राप्ति के समय, दंडित व्यक्ति द्वारा भोगी जाने वाली सज़ा की अवधि कम से कम छः माह बची हो अथवा वह आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा हो;
- (च) कि व्यक्ति को अंतरणकर्ता देश में जिन कृत्यों अथवा चूकों के लिए दंड दिया गया था, वे प्राप्तकर्ता देश में दांडिक अपराध हैं, अथवा यदि उसके अपने भूभाग में किए जाते तो दाण्डिक अपराध होते;
- (छ) दंडित व्यक्ति को सैन्य कानून के तहत दंडित न किया गया हो;
- (ज) प्राप्तकर्ता देश में दंडित व्यक्ति की हिरासत को अंतरित करने से अंतरणकर्ता देश की संप्रभुता, सुरक्षा अथवा किसी अन्य हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो;
- (झ) अंतरण के संबंध में दंडित व्यक्ति द्वारा सहमति दी जाती है अथवा, किसी भी संविदाकार देश द्वारा दंडित व्यक्ति की आयु अथवा शारीरिक या मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर, जरूरी समझे जाने पर संविदाकार देश के कानून के अनुसार उस व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सहमति दी गई हो; और
- (ञ) अंतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता देश अंतरण के संबंध में सहमत हों।

(2). आपवादिक मामलों में, यदि दंडित व्यक्ति द्वारा भोगे जा रहे दंड की शेष अवधि छः माह से कम हो तो भी अंतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता देश अंतरण के संबंध में सहमत हो सकते हैं।

#### अनुच्छेद 4

#### सूचना भेजने का दायित्व

(1). यदि दंडित व्यक्ति ने दण्डदाता देश को इस करार के तहत अन्तरित होने की इच्छा व्यक्त की हो तो, अंतरणकर्ता देश प्राप्तकर्ता देश को निम्नलिखित सूचना तथा दस्तावेज भेजेगा बशर्ते कि प्राप्तकर्ता या अन्तरणकर्ता देश में से किसी के भी द्वारा पहले ऐसा कोई निर्णय न लिया गया हो कि वह अन्तरण के लिए सहमत नहीं है :

- (क) दंडित व्यक्ति का नाम, लिंग और राष्ट्रीयता, जन्म तिथि एवं जन्म स्थान;
- (ख) प्राप्तकर्ता देश में उसका पता, यदि कोई हो;
- (ग) घटना के संक्षिप्त विवरण सहित उन तथ्यों का विवरण जिन पर दंड आधारित था;
- (घ) दंड की प्रकृति, समयावधि एवं प्रारंभ होने की तारीख;
- (ङ) निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा कानून के उन संगत उपबंधों की एक प्रति जिनके अंतर्गत दंडित व्यक्ति के खिलाफ दंड पारित किया गया है;
- (च) दंडित व्यक्ति की कोई डाक्टरी, सामाजिक अथवा अन्य कोई रिपोर्ट, जहां वह उसके आवेदन के निपटान अथवा उसकी परिरुद्धता की प्रकृति के निर्धारण के लिए प्रासंगिक हो;
- (छ) कोई अन्य सूचना जिसे प्राप्तकर्ता देश सभी मामलों में अपेक्षित सूचना के रूप में विनिर्दिष्ट करे कि यह संबंधित मामले में अंतरण की संभावना पर विचार करने के लिए जरूरी है और जिससे वह अपने कानून के अंतर्गत दंडित व्यक्ति को अंतरण के सम्पूर्ण परिणामों की जानकारी देने में सक्षम हो सके;
- (ज) अंतरित किए जाने वाले दंडित व्यक्ति अथवा अंतरणकर्ता देश के कानून के अनुसार उसकी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति का अनुरोध; और

(झ) किसी विचारण पूर्व नजरबंदी, क्षमा या दंड प्रवर्तन के लिए संगत किसी अन्य तथ्य को शामिल करते हुए, एक विवरण पत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि कितना दंड पूरा हो चुका है।

(2). इस करार के अधीन किसी अनुरोध पर कोई भी निर्णय लिए जाने के प्रयोजन से प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को निम्नलिखित जानकारी एवं दस्तावेज तभी भेजेगा जब प्राप्तकर्ता या अंतरणकर्ता देश ने पहले ही यह निश्चय कर लिया हो कि वह अंतरण से सहमत नहीं है :

- (क) एक विवरण अथवा दस्तावेज जो यह दर्शाता हो कि दंडित व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का एक नागरिक है;
- (ख) प्राप्तकर्ता देश के संगत कानून की एक प्रति जिसमें ऐसे कृत्य अथवा चूकें शामिल हैं, जिनके कारण अंतरणकर्ता देश में दण्ड पारित किया गया है, वे प्राप्तकर्ता देश के कानून के अंतर्गत अपराध माने गए हों अथवा यदि, ऐसे कृत्य अथवा चूकें इसके भू-भाग में घटित हों, तो उसे अपराध माना जाएगा;
- (ग) दंडित व्यक्ति के अन्तरण पर इस करार के अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 2 के प्रभाव का विवरण, यदि लागू हो, के सहित उसके अन्तरण के बाद प्राप्तकर्ता देश में सजा की अवधि एवं प्रवर्तन संबंधी किसी कानून अथवा विनियम के प्रभाव का विवरण;
- (घ) दण्डित व्यक्ति के अंतरण को स्वीकार करने के लिए प्राप्तकर्ता देश की सहमति और दंडित व्यक्ति की सजा के बाकी बचे हिस्से को शासित करने हेतु एक वचनबद्धता; तथा
- (ङ) कोई अन्य सूचना अथवा दस्तावेज जिसे अंतरणकर्ता देश आवश्यक समझे।

#### अनुच्छेद 5

#### अनुरोध एवं जवाब

(1). अंतरण के लिए अनुरोध लिखित रूप में, निर्धारित प्रपत्र, यदि कोई हो, में प्रस्तुत किया जाएगा और अनुरोधकर्ता देश के केन्द्रीय प्राधिकारी के माध्यम से राजनयिक माध्यम के द्वारा

1696 GI/10-2

प्रार्थित देश के केन्द्रीय प्राधिकारी को सम्बोधित किया जाएगा। जवाब उन्हीं माध्यमों से सूचित किए जाएंगे।

(2). इस अनुच्छेद के पैरा 1 के प्रयोजनार्थ, भारत के संबंध में, गृह मंत्रालय तथा बंगलादेश के संबंध में गृह मंत्रालय केन्द्रीय प्राधिकरण होगा।

(3). प्रार्थित देश शीघ्रतापूर्वक अनुरोधकर्ता देश को अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा कि वह प्रार्थित अंतरण के लिए सहमत है अथवा नहीं।

### अनुच्छेद 6

#### सहमति और इसका सत्यापन

(1). अंतरणकर्ता देश यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 (i) के अनुसार अंतरण के लिए सहमति देने वाला व्यक्ति, ऐसा स्वेच्छा से तथा इसके कानूनी परिणामों की पूरी जानकारी के साथ कर रहा है। इस प्रकार की सहमति देने की प्रक्रिया को अंतरणकर्ता देश के कानून द्वारा शासित किया जाएगा।

(2). अंतरणकर्ता देश, प्राप्तकर्ता देश को यह सत्यापित करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा कि सहमति, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में दी गई शर्तों के अनुसार प्रदान की गई है।

### अनुच्छेद 7

#### प्राप्तकर्ता देश के लिए अंतरण का प्रभाव

(1). प्राप्तकर्ता देश का सक्षम प्राधिकारी, इसके राष्ट्रीय कानून के तहत यथा अपेक्षित, इस करार के अनुच्छेद 8 में निर्धारित शर्तों के अनुसार किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश के द्वारा दण्ड का प्रवर्तन जारी रखेगा।

(2). इस करार के अनुच्छेद 10 के प्रावधानों के अध्यधीन, सज़ा का प्रवर्तन प्राप्तकर्ता देश तथा उस देश के कानून द्वारा शासित किया जाएगा।

### अनुच्छेद 8

#### सज़ा का सतत प्रवर्तन

- (1). प्राप्तकर्ता देश, अंतरणकर्ता देश द्वारा यथा-अभिनिर्धारित सज़ा की कानूनी प्रकृति एवं अवधि द्वारा आबद्ध होगा।
- (2). तथापि, यदि सज़ा की प्रकृति अथवा अवधि अथवा दोनों ही प्राप्तकर्ता देश के कानून से असंगत हों, अथवा इसके कानून में ऐसा अपेक्षित हो, तो वह देश न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश द्वारा, अन्तरणकर्ता देश की सहमति से सज़ा को अपने स्वयं के कानून द्वारा निर्धारित दण्ड अथवा उपाय में रूपान्तरित कर सकेगा। जहां तक इसकी प्रकृति एवं अवधि का प्रश्न है, दण्ड अथवा उपाय, यथासंभव, अंतरणकर्ता देश के अधिनिर्णय द्वारा आरोपित सज़ा के अनुरूप होगा। तथापि, यह अपनी प्रकृति अथवा अवधि द्वारा अंतरणकर्ता देश में आरोपित की गई सज़ा में वृद्धि नहीं करेगा।

### अनुच्छेद 9

#### अंतरणकर्ता देश के लिए सज़ा के समापन का प्रभाव

जब प्राप्तकर्ता देश इस करार के अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 1 (क) के तहत अंतरणकर्ता देश को यह अधिसूचित करता है कि दंड पूरा हो गया है, तो ऐसी अधिसूचना अंतरणकर्ता देश में उस सज़ा को समाप्त (रिहा) करने में प्रभावी मानी जाएगी।

### अनुच्छेद 10

#### माफी, राजक्षमा अथवा लघुकरण और निर्णय की समीक्षा

- (1). केवल अंतरणकर्ता देश ही निर्णय की पुनरीक्षा के लिए किसी आवेदन-पत्र पर निर्णय लेगा।
- (2). जब तक कि दोनों संविदाकार देश अन्यथा सहमत न हों केवल अन्तरणकर्ता देश ही अपने संविधान अथवा अन्य कानूनों के अनुरूप दंड की माफी, राजक्षमा प्रदान कर सकेगा अथवा दण्ड का लघुकरण कर सकेगा।
- (3). प्राप्तकर्ता देश अन्तरणकर्ता देश को बिना देरी किए इस निर्णय की सूचना देगा।

अनुच्छेद 11दण्ड के प्रवर्तन की समाप्ति

जैसे ही अंतरणकर्ता देश द्वारा किसी भी ऐसे फैसले अथवा उपाय की सूचना दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप दंड को कम अथवा उसका प्रवर्तन समाप्त किया गया हो, तो प्राप्तकर्ता देश दंड के प्रवर्तन को समाप्त कर देगा।

अनुच्छेद 12दण्ड के प्रवर्तन संबंधी सूचना

(1). प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को अधिसूचित करेगा :

(क) जब दण्ड का प्रवर्तन पूरा कर लिया गया हो; अथवा

(ख) "यदि दण्ड का प्रवर्तन पूरा होने से पहले दंडित व्यक्ति हिरासत से भाग जाता है। ऐसे मामलों में प्राप्तकर्ता देश को चाहिए कि वह दंडित व्यक्ति की गिरफ्तारी का हर-संभव प्रयास करे ताकि कैदी के भाग निकलने पर प्राप्तकर्ता देश के संगत कानून के अन्तर्गत किए गए अपराध के लिए कैदी पर अभियोग चलाया जा सके।"

(2). यदि अंतरणकर्ता देश द्वारा अपेक्षित हो, तो प्राप्तकर्ता देश दंड के प्रवर्तन के संबंध में एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

अनुच्छेद 13अभिवहन

1. यदि कोई भी संविदाकार देश दंडित व्यक्तियों के अंतरण के लिए किसी तीसरे देश के साथ कोई व्यवस्था करता है, तो दूसरा संविदाकार देश ऐसी व्यवस्था के अनुसरण में अपने भू-भाग से होकर अंतरित किए जाने वाले दंडित व्यक्तियों के अभिवहन को सुकर बनाने में सहयोग करेगा सिवाय इसके कि वह किसी ऐसे दंडित व्यक्ति के अभिवहन से इन्कार करे जो वहीं का राष्ट्रिक हो।

2. ऐसे अंतरण का इच्छुक संविदाकार देश दूसरे संविदाकार देश को ऐसे अभिवहन के बारे में अग्रिम नोटिस देगा।



### अनुच्छेद 14

#### लागत

अंतरणकर्ता देश के अनन्य भू-भाग में होने वाले व्ययों को छोड़कर, इस करार को लागू करने में आने वाले सभी व्यय प्राप्तकर्ता देश द्वारा वहन किए जाएंगे। तथापि, प्राप्तकर्ता देश, अंतरण में होने वाले सम्पूर्ण अथवा आंशिक व्यय की वसूली दंडित व्यक्ति अथवा किसी अन्य स्रोत से कर सकता है।

### अनुच्छेद 15

#### प्रादेशिक प्रयुक्ति

1. यह करार बंगलादेश लोक गणराज्य तथा भारत गणराज्य के भू-भाग में लागू होगा।
2. किसी भू-भाग, जिसके संबंध में इस अनुच्छेद के पैरा-1 के अनुसार विस्तार किया गया है, में इस करार की प्रयुक्ति राजनयिक चैनलों के माध्यम से अन्य भू-भाग में भी हो सकती है।

### अनुच्छेद 16

#### भाषा

अनुरोध एवं सहायक दस्तावेजों के साथ अंग्रेजी में अनुवाद संलग्न होगा।

### अनुच्छेद 17

#### लागू होने का दायरा

यह करार, इसके प्रभावी होने की तारीख से पहले या बाद में लगाए गए दण्ड के प्रवर्तन पर लागू होगा।

### अनुच्छेद 18

#### संशोधन

संविदाकार देशों द्वारा सहमत इस करार में कोई संशोधन अथवा आशोधन तभी प्रभावी होगा जब इसकी राजनयिक टिप्पणियों के आदान-प्रदान द्वारा पुष्टि कर दी जाएगी।

1696 GI/10-3

**अनुच्छेद 19****अंतिम प्रावधान**

- (1). यह करार, अनुसमर्थन के अध्यक्षीन होगा तथा अनुसमर्थन के लिखत का आदान-प्रदान करने की तारीख से प्रभावी होगा।
- (2). यह करार, किसी भी संविदाकार देश द्वारा दूसरे संविदाकार देश को करार के परिसमापन के अपने आशय की लिखित सूचना दिए जाने की तारीख से छह माह तक प्रभावी रहेगा।
- (3). किसी भी परिसमापन के बावजूद, यह करार उन दंडित व्यक्तियों के दंडों के प्रवर्तन पर लागू रहेगा जिन्हें इस परिसमापन के लागू होने की तारीख से पहले इस करार के अंतर्गत अंतरित किया गया हो।

इस करार के साक्ष्य के रूप में, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा इस संबंध में उचित प्रकार से प्राधिकृत किए जाने पर अधोहस्ताक्षरी ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसे 11 जनवरी 2010, को हिन्दी, बांगला तथा अंग्रेजी भाषाओं प्रत्येक में दो मूल प्रतियों में तैयार किया गया है। इसके सभी पाठ अधिप्रमाणित होने पर भी, व्याख्या में मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

ह/-

भारत-गणराज्य की सरकार की ओर से

ह/-

बंगलादेश लोक गणराज्य की सरकार की ओर से

[फा. सं. 17011/23/2009-पीआर]

डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**(CS Division)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th May, 2010

**G.S.R. 380(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Government of the Republic of Bangladesh and notifies the text of the treaty entered into between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Bangladesh as follows, namely:-

**"AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF PEOPLES'S REPUBLIC OF BANGLADESH. ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS"**

The Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of Bangladesh hereinafter referred to as the Contracting States;

**Desiring** to facilitate the social rehabilitation of sentenced persons in their own countries; and

**Considering** that this objective should be fulfilled by giving foreigners, who have been convicted and sentenced as a result of their commission of a criminal offence, the opportunity to serve their sentences within their own country;

**Have agreed** as follows:

## ARTICLE 1

### Definitions

For the purpose of this agreement:

- (a) 'judgment' means a decision or order of a court or tribunal imposing a sentence;
- (b) 'receiving State' means a State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve his sentence;
- (c) 'sentence' means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court or tribunal for a determinate period of time or for life imprisonment, in the exercise of its criminal jurisdiction;
- (d) 'sentenced person' means a person undergoing a sentence of imprisonment under an order passed by a criminal court including the courts established under the law for the time being in force in the Contracting States;
- (e) 'transferring State' means the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has been transferred.

## ARTICLE 2

### General Principles

1. A person sentenced in the territory of one Contracting State may be transferred to the territory of the other Contracting State in accordance with the provisions of this Agreement in order to serve the sentence imposed on him. To that end, he/she may express to transferring State or the receiving State his willingness to be transferred under this Agreement.
2. Transfer may be requested by any sentenced person who is a national of a Contracting State or by any other person who is entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State by making an application to the

Contracting State and in the manner prescribed by the Government of that Contracting State.

### ARTICLE 3

#### Conditions for transfer

1. A sentenced person may be transferred under this Agreement only on the following conditions:

- (a) the person is a national of the receiving State;
- (b) the death penalty has not been imposed on the sentenced person;
- (c) the judgment is final;
- (d) no inquiry or any other proceeding is pending against the sentenced person in the transferring State;
- (e) at the time of receipt of the request for transfer, the sentenced person still has at least six months of the sentence to serve or is undergoing a sentence of life imprisonment;
- (f) that the acts or omissions for which that person was sentenced in the transferring State are those which are punishable as a crime in the receiving State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
- (g) the sentenced person has not been convicted for an offence under the military law;
- (h) transfer or custody of the sentenced person to the receiving State shall not be prejudicial to the sovereignty, security or any other interest of the transferring State;
- (i) consent to the transfer is given by the sentenced person or, where in view of his age or physical or mental condition either Contracting State considering it necessary, by any other person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State ; and
- (j) the transferring and receiving State agree to the transfer

1696 GI/10-4

2. In exceptional cases the transferring and the receiving State may agree to a transfer even if the remaining period to be served by the sentenced person is less than six months.

#### ARTICLE 4

##### Obligation to furnish information

1. If sentenced person has expressed an interest to the sentencing State in being transferred under this Agreement, the transferring State shall send the following information and documents to the receiving State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:
  - (a) the name, sex and nationality, date and place of birth of the sentenced person;
  - (b) his/her address, if any, in the receiving State;
  - (c) a statement of the facts including a brief description of the incident upon which the sentence was based;
  - (d) the nature, duration and date of commencement of the sentence;
  - (e) a certified copy of the judgment and a copy of the relevant provisions of the law under which the sentence has been passed against the sentenced person;
  - (f) a medical, social or any other report on the sentenced person, where it is relevant for the disposal of his application or for deciding the nature of his confinement;
  - (g) any other information which the receiving State may specify as required in all cases to enable it to consider the possibility of transfer and to enable it to inform the sentenced person of the full consequences of transfer for him under its law;
  - (h) the request of the sentenced person to be transferred or of a person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the transferring State; and

- (i) a statement indicating how much of the sentence has already been served including information on any pre-trial detention, remission, or any other factor relevant to the enforcement of the sentence.
2. For the purposes of enabling a decision to be made on a request under this Agreement, the receiving State shall send the following information and documents to the transferring State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer;
- (a) a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the receiving State;
  - (b) a copy of the relevant law of the receiving State constituting the act or omissions, on account of which the sentence has been passed in the transferring State, as if such act or omissions were an offence under the law of the receiving State or would constitute an offence if committed on its territory;
  - (c) a statement of the effect of any law or regulation relating to the duration and enforcement of the sentence in the receiving State after the sentenced person's transfer including, if applicable, a statement of the effect of paragraph 2 of Article 8 of this agreement on his transfer;
  - (d) the willingness of the receiving State to accept the transfer of the sentenced person and an undertaking to administer the remaining part of the sentence of the sentenced person; and
  - (e) any other information or document which the transferring State may consider necessary.

## ARTICLE 5

### Request and replies

1. Requests for transfer shall be made in writing in the prescribed proforma, if any, and addressed through the central authority of the requesting State through diplomatic channels to the central authority of the requested State. Replies shall be communicated through the same channels.

2. For the purpose of paragraph 1 of this Article, the central authority shall be, in relation to India, the Ministry of Home Affairs, and in relation to Bangladesh shall be the Ministry of Home Affairs.

3. The requested State shall promptly inform the requesting State of its decision whether or not to agree to the requested transfer.

## **ARTICLE 6**

### **Consent and its verification**

1. The transferring State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with paragraph 1 (i) of Article 3 of this Agreement, does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the transferring State.

2. The transferring State shall afford an opportunity to the receiving State to verify that the consent is given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 of this Article.

## **ARTICLE 7**

### **Effect of transfer for the receiving State**

1. The competent authorities of the receiving State shall continue the enforcement of the sentence through a court or administrative order, as may be required under its national law, under the conditions set out in Article 8 of this Agreement.

2. Subject to the provisions of Article 10 of this Agreement, the enforcement of the sentence shall be governed by the law of the receiving State.

## **ARTICLE 8**

### **Continued enforcement of sentence**

1. The receiving State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the transferring State.



2. If however, the sentence is by its nature or duration or both, incompatible with the law of the receiving State, or its law, so requires, that State may, by court or administrative order, adapt the sentence to a punishment or measure prescribed by its own law with the consent of the transferring State. As to its nature and duration the punishment or measure shall, as far as possible, correspond with that imposed by the judgment of the transferring State. It shall however not aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed in the transferring State

## ARTICLE 9

### Effect on completion of sentence for the transferring State

When the receiving State notifies the transferring State under paragraph 1(a) of Article 12 of this Agreement that the sentence has been completed, such notification shall have the effect of discharging that sentence in the transferring State.

## ARTICLE 10

### Pardon, amnesty or commutation and review of judgment

1. The transferring State alone shall decide on any application for the review of the judgment.
2. Unless both the Contracting States otherwise agree, the transferring State alone may grant pardon, amnesty or commutation of the sentence in accordance with its Constitution or other laws.
3. The transferring State shall inform the receiving State of such decision without delay.

## ARTICLE 11

### Termination of enforcement of sentence

The receiving State shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the transferring State of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.

1696 GI/10-5

**ARTICLE 12****Information on enforcement of sentence**

1. The receiving State shall notify the transferring State:
  - (a) when the enforcement of the sentence has been completed; or
  - (b) If the prisoner escapes from custody before enforcement of the sentence has been completed. In such cases the receiving State shall make every effort to have the prisoner arrested so that the prisoner be prosecuted for committing an offence under the relevant law of the receiving State on escape of prisoner.
2. The receiving State shall furnish a special report concerning the enforcement of the sentence, if so required by the transferring State.

**ARTICLE 13****Transit**

1. If either Contracting State enters into arrangement for the transfer of sentenced persons with any third State, the other Contracting State shall cooperate in facilitating the transit through its territory of the sentenced persons being transferred pursuant to such arrangements, except that it may refuse to grant transit to any sentenced person who is one of its own nationals.
2. The Contracting State intending to make such a transfer shall give advance notice to the other Contracting State of such transit.

**ARTICLE 14****Costs**

Any costs incurred in the application of this Agreement shall be borne by the receiving State, except costs incurred exclusively in the territory of the transferring State. The receiving State may, however, seek to recover all or part of the costs of transfer from the sentenced person or from any other source.

## **ARTICLE 15**

### **Territorial application**

1. This Agreement shall apply to the territory of the Republic of India and of the People's Republic of Bangladesh.
2. The application of this Agreement to any territory, in respect of which extension has been made in accordance with paragraph 1 of this Article, may be communicated to the other through the diplomatic channels.

## **ARTICLE 16**

### **Language**

Requests and supporting documents shall be accompanied by a translation into English.

## **ARTICLE 17**

### **Scope of application**

This Agreement shall be applicable to the enforcement of sentences imposed before or after the entry into force of this Agreement.

## **ARTICLE 18**

### **Amendments**

Any amendments or modifications to this Agreement agreed by the Contracting States shall come into effect when confirmed by an exchange of diplomatic notes.

## **ARTICLE 19**

### **Final provisions**

1. This Agreement shall be subject to ratification and shall enter into force on the date on which instruments of ratification are exchanged.

2. The Agreement shall continue to remain in force until six months from the date upon which either Contracting State gives written notice to the other Contracting State of its intention to terminate it.

3. Notwithstanding any termination, this Agreement shall continue to apply to the enforcement of sentences of sentenced persons who have been transferred under this Agreement before the date on which such termination takes effect.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at New Delhi on the 11<sup>th</sup> day of January in the year 2010, in two originals each in Hindi, Bangla and English languages. All the texts being equally authentic, in case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**Sd/-**

**For the Government of the Republic of India**

**Sd/-**

**For the Government of the  
People's Republic of Bangladesh "**

[F. No. 17011/23/2009-PR]

Dr. NIRMALJEET SINGH KALSI, Jt. Secy.